फरीदाबाद में पानी की पाइप लाइन तोड़ो और पैसा कमाओ

रेनीवेल लाइन टूटने पर एमसीएफ अफसरों की होती पौ-बारह

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शहर के एक बड़े हिस्से में पांच दिनों तक पानी नहीं आया। जनता को बताया गया कि ददसिया रेनीवेल की पाइप लाइन टूटने से यह स्थिति पैदा हुई लेकिन दरअसल पाइपलाइन टूटने और उसकी आड़ में कमाई का घिनौना खेल खेलने का मामला भी सामने आ रहा है। पाइप लाइन टूटने के मामले में हूडा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और संबंधित एक्सईएन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से संबंधित फाइल एमसीएफ के चीफ इंजीनियर के कमरे से गायब पाई गई, जबकि उस फाइल पर कमिश्नर यशपाल यादव के हस्ताक्षर थे।

6 मार्च 2021 को रेलीवेल की पाइप लाइन पलवली गांव के पास उस वक्त टूट गई जब वहां पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हूडा) बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला बना रहा था। ददसिया में बने एमसीएफ के रेनीवेल की पाइप लाइन पलवली गांव से निकलती है लेकिन रहस्यमय हालात में पाइप लाइन टूट गई। इस पाइप लाइन से सेक्टर 14, 19, 29, 30, 31, 21ए, बी,सी,डी, सेक्टर 46,48, एनआईटी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के अलावा डबुआ, सारन, पर्वतीय कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी में भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया। लाखों घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी।

सेक्टर 21 सी और 46 के लोगों ने 9 मार्च को बूस्टर स्टेशन पर जाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद एमसीएफ में इस पाइप लाइन को बनाने की कार्रवाई तेज हुई। एमसीएफ अफसरों के बीच बने वाट्सऐप ग्रुप पर कमिश्नर यशपाल यादव और चीफ इंजीनियर के बीच काम को तेज करने को लेकर चैट के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान होता रहा। आखिरकार बुधवार शाम को सारे शहर की पेयजल आपूर्ति सामान्य हो सकी।

पानी की आड़ में सरकारी पैसे की लूट

फरीदाबाद की लाइफलाइन बने रेनीवेल की पाइप लाइन साल में एक या दो बार कहीं न कहीं लीकेज या क्षतिग्रस्त जरूर होती है। इस बार भी इसकी मरम्मत पर करीब सात लाख रुपये खर्च हुए हैं। रेनीवेल का काम इंजीनियरिंग ब्रांच के एसडीओ नवल सिंह नरवत के पास है। यही शख्स पिछले चार-पांच साल से रेनीवेल का इंचार्ज है। कितने ही चीफ इंजीनियर इंजीनियरिंग ब्रांच से बदल

गए लेकिन एसडीओ नवल सिंह नरवत उसी कुर्सी पर विराजमान है। बी. के. कर्दम जो एमसीएफ में हुए कई घोटालों की जांच का सामना कर रहा है और सबसे भ्रष्ट अधिकारी माना जाता है, वह दो बार चीफ इंजीनियर बना और हटा लेकिन नवल सिंह उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले रेनीवेल की पाइप लाइन सन् 2020 में भी दो बार, 2019 में तीन बार, 2018 में दो बार, 2017 में दो बार टूट चुकी है। हर बार कम से कम पांच लाख रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये खर्च करा कर जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि हर बार यह पाइप लाइन कोई ट्रक, कोई खंभा गिरने या किसी अन्य विभाग का काम होने के दौरान ही टूटती है। यानी गेम इतना सेफ साइड खेला जाता है कि पाइप लाइन टूटने का जिम्मेदार कोई और होता है और पैसा एमसीएफ का खर्च होता है।

अडानी पीएनजी गैस की पाइप लाइन गुजरात से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में फैली है लेकिन अडानी गैस की पाइप लाइन टूटने या फटने की खबर कभी-कभार सुनाई देती है लेकिन एमसीएफ रेनीवेल के पाइप लाइन टूटने की खबर साल में कम से कम दो बार जरूर सुनाई देती है।

रेनीवेल और उसकी पाइप लाइन एमसीएफ का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था जीरो है।

कहां गुम हो गई फाइल

मजदूर मोर्चा संवाददाता ने एमसीएफ के चीफ इंजीनियर रामजी लाल से बुधवार को मुलाकात की। इस संवाददाता ने चीफ इंजीनियर से रेनीवेल पाइप लाइन टूटने को लेकर लिए गए एक्शन की जानकारी मांगी। चीफ इंजीनियर ने बताया कि कमिश्नर यशपाल यादव ने आज ही आदेश दिए हैं कि हूडा के अफसरों की लापरवाही की वजह से पाइप लाइन टूटी है, इसलिए उन पर एक्शन किया जाए। इसके बाद उस आदेश के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए चीफ इंजीनियर उस फाइल को तलाशने लगे। लेकिन वो फाइल उन्हें मिली ही नहीं। इस समाचार के लिखे जाने तक वह फाइल चीफ इंजीनियर को नहीं मिली थी। चीफ इंजीनियर एमसीएफ कर्मचारियों की इस हरकत से परेशान नजर आए कि ठेकेदार या पार्षद अपने काम या इलाके से संबंधिक वर्क आर्डर की फाइल लेकर खुद ही चले आते हैं जबकि सरकारी दफ्तरों में फाइल भेजने-मंगाने का एक सिस्टम बना हुआ है लेकिन एमसीएफ में सारी फाइल या तो ठेकेदार या फिर पार्षद के हाथ में होती है। इस संवाददाता के सामने ही दो पार्षद सीधे फाइल लेकर काम कराने आ गए। चीफ इंजीनियर ने उनको इस तरह फाइल लेकर न आने की नसीहत दी।

पानी के खेल में मजा ही मजा

रेनीवेल पाइप लाइन टूटने पर उसकी मरम्मत में कमीशनबाजी तो है ही लेकिन जब यह पाइप लाइन गर्मी में टूटती है तो उसका मजा एमसीएफ के भ्रष्ट अफसरों के लिए दोगुना हो जाता है। दरअसल, फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर पानी सप्लाई के प्राइवेट प्लांट लगे हुए हैं। जहां बोरवेल के अलावा एमसीएफ के ट्यूबवेलों का पानी और नहरों का पानी चोरी करके लाया जाता है। फिर उनमें क्लोरीन डालकर बोतलों में भरकर शहर में सप्लाई किया जाता है। गर्मी में फरीदाबाद शहर इसी पानी पर जिन्दा रहता है। जबकि एमसीएफ के ट्यूबवेल या तो खराब रहते हैं या पानी की पाइप लाइन कहीं टूटी होती है और कुछ बूस्टर स्टेशनों पर तकनीकी समस्या बनी रहती है। इस तरह गर्मियों में फरीदाबाद में पानी के खेल का मजा एमसीएफ के बेईमान अफसरों की कमाई का मोटा जरिया है।

कहां जाते हैं हर साल लाखों रुपये

नगर निगम के बजट में हर साल शहर की पेयजल सप्लाई पर लाखों रुपये का प्रावधान रहता है। अभी हाल ही में पेश किए गए एमसीएफ के 2021-22 के बजट में शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए 1285 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसी तरह 2020-21 में यानी पिछले साल 11765 लाख रुपये की व्यवस्था पेयजल के लिए की गई थी। इसी तरह 20,000 लाख रुपये अमृत योजना के तहत मिलने की घोषणा की गई थी। अमृत योजना केन्द्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट है। नगर निगम पार्षद या मेयर अगर चाहते तो पिछले साल इस मद में रखे गए पैसों से पूरे शहर की पेयजल आपूर्ति को ठीक कर सकते थे। लेकिन एमसीएफ के बेईमान अफसरों ने पार्षदों और मेयर से मिलकर इस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया। किसी पार्षद ने गलती से भी पिछले साल पेयजल आपूर्ति पर खर्च किए गए पैसों के बार में पूछताछ नहीं की।

2019-20 में एमसीएफ ने शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए 112 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा था। उस साल एमसीएफ को केन्द्र से अमृत योजना में 235 करोड़ मिले थे। कहां गए वो पैसे...किसी ने यह सवाल नहीं पूछा।

2018-19 के बजट में पानी की आपूर्ति पर 126 करोड़ खर्च किए गए। हालांकि 2017-18 की तुलना में उस साल 28 करोड़ रुपये घटा दिए गए थे। उस साल से पानी के मद में बजट लगातार कम होता जा रहा है।

2017-18 के बजट में पेयजल आपूर्ति के लिए 101 करोड़ रुपये रखे गए थे। साल दर साल एमसीएफ बजट के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नगर निगम में पानी की आड़ में सरकारी पैसे की लूट बड़े पैमाने पर की जा रही है। हर साल बजट में मिलने वाली राशि का अगर आधा हिस्सा ही एमसीएफ के बेईमान अफसर ईमानदारी से खर्च कर दें तो शहर में पानी का संकट खत्म हो जाएगा लेकिन चूंकि ठेकेदार, भ्रष्ट अफसर, पानी बेचने वाला माफिया गठजोड़ बनाकर इस अपराध को जिस संगठित तरीके से कर रहे हैं, उससे कोई बड़ा अफसर लड़ नहीं सकता।

पंचायत चुनाव: सरपंचों पर नहीं, अपने अफसरों पर ज्यादा भरोसा है खट्टर को

पंचायत चुनाव ठंडे बस्ते में डालने से गांवों में पंचायतों के मामूली काम भी रुके

मजदूर मोर्चा संवाददाता

बल्लभगढ़: दूसरे राजनीतिक दलों में लोकतंत्र तलाशने वाली भाजपा एक-एक कर लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधिकार किस तरह छीनने में लगी है, उसका ताजा उदाहरण हरियाणा में पंचायत चुनाव न होना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक से पत्रकार पूछ चुके हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे, खट्टर का कहना है कि जब होने होंगे तो हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, प्रदेश भर के पंचायत अधिकारियों के पास गांवों के सरपंचों ने अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि चुनाव कब होंगे ?

अगला चुनाव न होने तक गांव का सरपंच तो वही रहेगा लेकिन उसे गांव में कोई विकास कार्य कराने का अधिकार उसे नहीं होगा। वह अपने अधूरे कार्यों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बैंक से लेन-देन नहीं कर सकता। हां, वह केवल किसी सामान्य दस्तावेज पर अपनी मोहर लगा सकता है, सरकारी काम-काज में इस्तेमाल नहीं कर सकता।

सरकारी अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा

गांव में होने वाले हर विकास कार्य का पूरा जिम्मा ब्लॉक पंचायत अधिकारी और ग्राम सचिव का होगा, उन्हीं की देखरेख में सभी कार्य किए जाएंगे। जैसे सफाई कर्मचारियों की सैलरी, काम करने वाले मजदूर और मिस्त्रियों को दिहाड़ी देना। ईंटें, टाइलें, रोड़ी क्रेसर आदि सामान की बिल अदायगी पंचायत अधिकारी ही करेगा। यानि लोकतंत्र की बात करने वाली भाजपा सरकार को चुने हुए सरपंचों पर भरोसा नहीं है। जबकि सरकार के भ्रष्ट सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों पर उसका ज्यादा भरोसा है।

हालांकि अफसरों को खाने-कमाने का रास्ता मिलने के बावजूद गांवों में बड़े विकास कार्य अधिकारी भी नहीं करा सकेंगे। जैसे किसी नये प्रोजेक्ट पर काम करने का अधिकार ब्लॉक पंचायत अधिकारी और ग्राम सचिव का भी नहीं होगा। जैसे स्कूल में कोई कमरा बनवाना है, किसी नई सड़क का निर्माण कराना है, कोई चौपाल बनवाना आदि। 1994 में गांवों में हुई वॉर्ड बंदी के समय ही ये नियम बना दिए गए थे, लेकिन सरपंचों के बस्ता जमा होने से पहले ही चुनावों की तिथि घोषित कर दी जाती थी, लेकिन इस बार बस्ता जमा करो अभियान तो चला दिया गया है लेकिन चुनावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

हरियाणा में पंचायत चुनाव कब होंगे, जब बल्लभगढ़ के पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा-अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब होने होंगे सबको पता चल जाएगा। हरियाणा सरकार पंचायत चुनावों को लेकर अपना मत स्पष्ट कर पाने में असमर्थ है। देखना है खट्टर सरकार कब पंचायत चुनावों की सुध लेगी? कब तक गांव के विकास कार्यों की औपचारिकता पंचायत अधिकारी और ग्राम सचिव निभाते हैं।

देखी-सुनी

खबरीलाल

यशपाल की तेज गेंदबाजी

आईएएस यशपाल यादव की तरह-तरह की दिलचस्पी चर्चा का विषय है। यशपाल डीसी होने के अलावा नगर निगम फरीदाबाद के कमिश्नर भी हैं। लेकिन उनका ज्यादा समय या तो क्रिकेट डिप्लोमेसी या फिर एमसीएफ में बीत रहा है। उपायुक्त कार्यालय से सीधे जुड़े अफसरों को यशपाल यादव का चेहरे देखे कई-कई दिन बीत जाते हैं। शहर में इस समय क्रिकेट अफसरों से जनसंपर्क बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। उद्योगपतियों की कंपनियों के साथ डीसी इलेवन के मैच अक्सर होने लगे हैं, जिसमें यशपाल यादव को बॉलिंग करते देखा जा सकता है। क्रिकेट से जो समय बचता है वह समय एमसीएफ के हिस्से में आता है। फरीदाबाद में टैक्स वसूली और रिकवरी जरूर बढ़ी है लेकिन शहर की खटारा सड़कों, बहते सीवरों, अनियमित पेयजल आपूर्ति की सुध तो यशपाल यादव को भी नहीं है। एमसीएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी देने से सरकार को जरूर फायदा हुआ है लेकिन जब तक जनता को फायदा होता हुआ न दिखे तो डीसी का एमसीएफ में होना न होना बेकार है।

बिल्डरों का बदलता रुख

फरीदाबाद की बिल्डर लॉबी हवा का रुख पहचानने में माहिर है। तमाम बिल्डरों ने कांग्रेस के उन असरदार नेताओं से फिर से संपर्क करना शुरू कर दिया है जिनको अभी कल तो वो घास डालने को तैयार नहीं थे। गांधी परिवार के नजदीक माने जाने वाले एक कांग्रेस नेता को ऐसे-ऐसे बिल्डरों के फोन आ रहे हैं, जिनके नाम उन बिल्डरों की फोन बुक तक से गायब थे। ऐसे ही एक कांग्रेस नेता को हाल ही में एक नामी बिल्डर के दफ्तर में कॉफी के घूंट उतारते देखा गया। अभी पिछले महीने तक यह बिल्डर प्रॉपर्टी डीलर के रूप में मशहूर एक केन्द्रीय मंत्री के पैसे को निवेश करने में जुटा हुआ था। बिल्डर लॉबी का मानना है कि हरियाणा में देर-सवेर तख्ता पलट होने पर कांग्रेस आ सकती है और अगला चुनाव जब भी होगा हरियाणा में कांग्रेस की वापसी तय है। ऐसे में समय रहते ही संपर्क ठीक कर लिये जायें।

इस डेयरी वाले पर विज हैं कुर्बान

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज खुद को मनोहर कैबिनेट का सबसे ईमानदार मंत्री कहते हैं लेकिन जब खुद का इलाज कराना हो तो सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट में भर्ती होते हैं। लेकिन उनकी ईमानदारी का पर्दाफ़ाश करती हुई एक घटना सामने आई है। अंबाला कैंट सदर बाज़ार में राजोविला पर अवैध क़ब्ज़े का मामला सामने आया है। यह जगह आरएसएस- भाजपा के पूर्वज रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार से जुड़े लोगों की है। इस पर अशोक डेयरी वाले का क़ब्ज़ा है। अब आप पूछिए कि अशोक डेयरी वाला कौन है। दरअसल, अशोक डेयरी वाला विज के चुनाव को हर तरीक़े से मैनेज करने के लिए जाना जाता है। इसलिए पुलिस उसे हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अंबाला कैंट के अधिकारी इस घटना का पूरा मज़ा लेकर कहते हैं - यह आरएसएस- भाजपा का आंतरिक मामला है। भला इसमें हम क्यों दखल दें। आपको पता चल ही गया होगा कि ये आंतरिक मामले की बात किस संदर्भ में कही गई है।

वक्त कैसे बदलता है

चुनाव में जय श्रीराम का नारा लगाने को दी गई चुनौती की याचिका को चीफ जस्टिस बोबडे की बेंच ने ख़ारिज कर दिया। ...यही बोबडे 2017 में उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने कहा था कि चुनाव एक सेकुलर प्रक्रिया है और उसमें धर्म का नारा लगाना एक भ्रष्ट प्रक्रिया है।...आप समझिए कि वक़्त कैसे बदलता है। चीफ़ जस्टिस बोबडे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कितने ही विवादास्पद टिप्पणियों के लिए याद किए जाएँगे। अदालतों की गिरती साख के लिए अगर कोई ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा तो उसमें बोबडे का नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06